शिक्षा और शिक्षकों की बेहतरी की बेहतर कोशिशें

श्रुति वर्मा

जिस स्वर्णिम मध्यप्रदेश की संकल्पना को साकार करने का संकल्प लेकर प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है, उसे साकार करने के दो कारक तत्व हैं– हर बच्चे को शिक्षा और आम आदमी का मददगार सुशासन। शिक्षा जीवन का वह संस्कार है जिससे मनुष्य के उन सभी नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास होता है जो सुशासन रचने के लिए जरूरी होते हैं। इन्हीं तानों-बानों से बुना जाता है एक प्रगति की ओर बढ़ता मध्यप्रदेश जिसमें खुशहाली की स्वर्णिम आभा का उजास उसके बाशिन्दों को आनंदित करता है।

शिक्षा विभाग की जानकारी एक क्लिक पर

www.mp.gov.in/educationportal केवल एक वेब पोर्टल नहीं है। ये एक और कदम है मध्यप्रदेश सरकार का सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने का। साथ ही ये एक साझा मंच है शिक्षा जगत से जुड़े सभी लोगों के लिए। ये वेबसाइट ई-गवर्नेंस की बेहतरीन मिसाल बन चुकी है, जो शिक्षकों के साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी लाभप्रद साबित हो रही है।

मध्यप्रदेश का शिक्षा विभाग अन्य विभागों की तुलना में काफी बड़ा है और जब प्रदेश में हर तबके की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है तो इस विभाग की जिम्मेदारियाँ बढ़ना भी लाजमी है। ऐसे में छोटी से छोटी चूक को रोकने के लिए ये पहल की गई है। जो केवल एक पोर्टल न होकर पूरे शिक्षा विभाग का बही-खाता भी होगा, जिसमें विभाग की हर छोटी-बड़ी जानकारी उपलब्ध है। इसकी शुरुआत हुई है यूनिक कोड से। ये कोड विभाग के हर शिक्षक और कर्मचारी को आवंटित किया गया है। इसके बाद शिक्षा जगत से जुड़े लोग केवल एक क्लिक से खुद से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। वेतन संबंधी विवरण, वेतन पर्ची एवं वार्षिक इंक्रम का स्टेटमेंट भी इसमें शामिल है। विभाग से जुड़े सभी निर्देश भी इस पोर्टल पर जारी होते हैं। इसके तकनीकी संचालक सुनील जैन की मानें तो विभाग को नया प्लेटफॉर्म मिला है। जहाँ

छाया : प्रहलाद कुमार

सब एक साथ नजर आते हैं। तकरीबन डेढ़ साल की मेहनत से शुरू हुआ ये पोर्टल खासा बिजी भी रहता है। तैयार होने के साथ ही इसे तीन लाख से ज्यादा यूजर्स जो मिल गए हैं। यह पोर्टल एक है, लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं–

- स्थापना संबंधी काम में पारदर्शिता
- नियत समय पर पदोन्नतियाँ, क्रमोन्नतियाँ
- न्यायपूर्ण स्थानांतरण की व्यवस्था
- नियत समय पर वेतन वृद्धि
- समय पर पेंशन
- मैन पावर प्लानिंग
- विषयवार पदस्थापना

सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण

श्री सुनील जैन कहते हैं कि इन सुविधाओं के बाद शिक्षा विभाग में हुए बदलावों की पल-पल जानकारी आसान हो गई है। अब शिक्षकों की कमी को पूरा करना भी आसान हो गया है। इसके बाद अतिथि विद्वानों के नाम पर होने वाले हेरफेर पर भी अंकुश लग पाया है।

इस पोर्टल के जरिए शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को भी समय पर वेतन मिलना सुनिश्चित हो पाया है। खुद से जुड़ी जानकारी लेने के अलावा शिक्षक अपनी शिकायतें भी यहाँ दर्ज करवा सकते हैं। एक सरकारी स्कूल की शिक्षक आशा शर्मा का कहना है कि अब वो काम भी आसान हो गए हैं जिनमें पहले हफ्ते लग जाते थे। इससे ये तो साबित हो ही गया है कि जब अन्य कामों की फिक्र नहीं होगी तो शिक्षक आसानी से शिक्षा पर ध्यान दे पाएँगे।

श्री जैन कहते हैं कि तनाव से मुक्ति मिलने पर क्वालिटी कंट्रोल पर जोर भी बढ़ा है। यही इस पोर्टल से भी हो रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में मॉनीटरिंग भी तेज और सख्त हो गई है। पोर्टल से सभी स्कूलों को एक जैसा टेस्ट पेपर दिया जाता है। टेस्ट के बाद परिणामों की जानकारी पोर्टल पर देना सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य है। इसका खास मकसद बेहतर परिणाम और विद्यार्थियों का सही आकलन करना है। खास किस्म की पहचान (यूनिक आईडी) से शिक्षकों की सहूलियत बढ़ गई है तो विद्यार्थियों के लिए भी ये काफी सार्थक है। विद्यार्थियों की संख्या तो यहाँ है ही, कस्बे के कितने बच्चे स्कूल जाने लायक हैं, इसका आँकड़ा भी साइट पर मिल जाएगा, ताकि वे भी शिक्षा से वंचित न रह जाएँ। ड्रॉप आउट्स का डाटा भी है और उन्हें स्कूल भेजने के प्रयासों की जानकारी भी ताकि स्कूल चलें हम का सपना पूरी तरह साकार हो पाए। विद्यार्थियों की संख्या शिक्षकों से कहीं ज्यादा

होने के बावजूद वे सभी इस साइट पर एनरॉल हैं। वे जब चाहें इस साइट पर लॉग करके अपने परिणाम भी जान सकते हैं। आठवीं के छात्र आशीष शंकर के मुताबिक अब वे खुद अपना आकलन प्रदेश के हर विद्यार्थी से कर सकते हैं।

नया सत्र शुरू होने के बाद किताबें न मिलने की शिकायत भी अब दूर हो गई है। इस पोर्टल पर हर कक्षा की सभी पाठ्यपुस्तकें पूरी-पूरी उपलब्ध हैं। इसकी साथ ही मल्टी मीडिया से जुड़ी तमाम जानकारी भी इस वेबसाइट से ले सकते हैं। इन सब अनूठी बातों के चलते वेबसाइट को कई सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। राज्य शिक्षा केन्द्र के आयुक्त मनोज झालानी ऐसे पहले ब्यूरोक्रेट हैं जो आईटी की दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिका पीसी क्वेस्ट के कव्हर पेज पर कब्जा जमा चुके हैं।

पत्रिका के जुलाई, 2010 के अंक में इस पोर्टल को काफी सराहना मिली है। मध्यप्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने भी इसे आईटी फॉर मासेस अवार्ड से नवाजा है, लेकिन वेबसाइट का सफर इतने पर ही नहीं थमा है। अब भी इस पर नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। जो गाँव के शिक्षक और विद्यार्थियों को ज्यादा कम्प्यूटर फ्रेंडली बना सके।

शिक्षकों को सहूलियतें

इस वर्ष स्कूल शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से विद्यार्थियों का नेत्र परीक्षण एवं दृष्टि दोष पाये जाने पर उन्हें निःशुल्क चश्मा और दवाओं का वितरण करेगा। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आगामी 15 अगस्त तक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। 15 सितम्बर तक प्रशिक्षित शिक्षक विद्यालय स्तर पर बच्चों का नेत्र परीक्षण कर दृष्टिदोष वाले विद्यार्थियों को चिन्हित करेंगे। 30 सितम्बर तक विकासखंड स्तर पर आयोजित शिविरों में विद्यार्थियों का नेत्र परीक्षण किया जायेगा।

सभी शासकीय शालाओं की कक्षा-एक से आठवीं तक की लगभग साठ लाख बालिकाओं को दो जोड़ गणवेश निःशुल्क प्रदाय किये जा रहे हैं। गणवेश में प्रयुक्त होने वाले कपड़े की गुणवत्ता में और अधिक सुधार

छाया : संजय कुमार

लाने हेतु विगत वर्ष की अपेक्षा इस साल विशेष प्रयास किये गये हैं। राज्य शासन ने इस वर्ष 15 अगस्त तक सभी स्कूलों में गणवेश वितरण कराने की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की हैं।

राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष भी कक्षा पाँचवीं उत्तीर्ण करके गाँव के बाहर शासकीय स्कूल में कक्षा छठवीं में जाने वाली तथा कक्षा नवमीं से बारहवीं तक पढ़ने वाली लगभग एक लाख बालिकाओं को निःशुल्क साईकिल प्रदाय किये जाने की योजना पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

राज्य शासन ने छब्बीस जिलों के पचास हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया है। इन स्कूलों को वर्ष 2010-11 से उन्नत कर प्रारंभ करने की अनुमति जारी की गई है।

जुलाई माह में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने अपने रवैये से साफ कर दिया था कि शिक्षा से जुड़े कामों को महज रस्म अदायगी न समझा जाए।

सालों से संविदा शिक्षक अध्यापक संवर्ग में शामिल होने का इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार तो अब खत्म हो ही गया है। उन्हें अध्यापकों की तरह तकरीबन सभी भत्ते मिलने लगे हैं। इसके बाद विद्यार्थियों को शिक्षा देने में उनका ध्यान लगने लगा है। मध्यप्रदेश गुरुजी संघ के अध्यक्ष संदर्भ सिंह बघेल को उम्मीद है कि जैसे संविदा शिक्षकों को अध्यापक वर्ग में शामिल किया गया है। उसी तरह गुरुजी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले गुरुजियों को संविदा शिक्षक मानने की उनकी माँग भी जल्द ही पूरी होगी।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में शिक्षा की अलख जगाने का काम केवल अध्यापक वर्ग का नहीं है। संविदा शिक्षक, गुरुजी और औपचारिकेत्तर शिक्षाकर्मी भी इस काम में बराबरी से जुटे हैं। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का उजियारा फैलाने का जिम्मा उन्हीं का है। मध्यप्रदेश सरकार ने जितनी गंभीरता से विद्यार्थियों के स्कूल जाने और अच्छे परिणामों को लिया है, उतनी ही संवेदना इन शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने में भी दिखाई है। पश्चिमी यूरोप के तीन देशों की यात्रा से लौटते ही मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने सबसे पहले स्कूल चलें हम अभियान की समीक्षा की और उसकी अगली ही कैबिनेट बैठक में संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक वर्ग में शामिल करने का फैसला सुना दिया। साथ ही अध्यापक संवर्ग को महँगाई भत्ते में नौ प्रतिशत वृद्धि का लाभ देने का निर्णय भी लिया है।

देवी सरस्वती की सबसे पहले आराधना करने वाली मध्यप्रदेश सरकार ने शिक्षकों को भी सरआँखों पर बिठाया है। उनकी माँगों को दूर करने की त्वरित गति और समय-समय पर समीक्षा से ये साफ जाहिर भी होता है। शिक्षा हर एक के लिए और स्कूल चलें हम अभियान के लिए मध्यप्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता भी झलकती है। जो शिक्षकों के हर तबके को बराबरी का दर्जा और सम्मान देने के लिए प्रयासरत है।

(लेखिका युवा पत्रकार हैं।)